



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25 1989/आश्विन 3, 1911
No. 509] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 1989/ASVINA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1989

आय-कर

सं. का. नि. 853 (अ):—आय पर और पूंजी पर करों की
बाबत दोहरे कराधान के परिवर्तन और राजस्व अर्पण के निवारण
के लिए भारत गणराज्य की सरकार और डेनमार्क राज्य की सरकार के
बीच उपावृद्ध कंवेन्शन उक्त कंवेन्शन के अनुच्छेद 30 के पैरा 1 की
अपेक्षानुसार दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक-दूसरे को सांविधानिक
अपेक्षाओं के पूरा होने की अधिसूचना दिए जाने पर, 13 जून, 1989
को प्रवृत्त हो गया है ;

अब, अतः केन्द्रीय सरकार के आय-कर अधिनियम, 1961 (1961
का 43) की धारा 90 कम्पनी (लाभ) अधिनियम, 1964

(1964 का 7) की धारा 24क और धा-कर अधिनियम, 1967 (1967
का 27) की धारा 44क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए,
यह निदेश देती है कि उक्त कंवेन्शन के सभी उपबन्धों का भारत संघ में
कार्यान्वित किया जाएगा।

उपरोक्त

भारत गणराज्य और डेनमार्क किंगडम के बीच आय तथा पूंजी पर
करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अर्पण के
रोकने के लिए अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क किंगडम की सरकार आय
तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व
के अर्पण के रोकने के लिए अभिसमय सम्पन्न करने का इच्छा से
नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :—

अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत कार्य-धैर्य

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों
में से किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

प्रतिपक्ष के अधिनियम को ध्यान में रख कर

जिस कानून पर यह अधिनियम लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :

(क) भारत में :

- (i) आयकर जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत उस पर लगने वाला कोई भी अधिभार शामिल है ;
- (ii) कम्पनी (लाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला अधिकार ;
- (iii) धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 24) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला धनकर ;

जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा ।

(ख) डेनमार्क में :

- (1) राज्य को देय आयकर (इन्डोकोमोस्कातेन) (निल-स्तातेन) ;
 - (2) नगर पालिका आयकर (तेनकोमुसाल इतकोमस्तस्काट) ;
 - (3) देश की नगरपालिकाओं को देय आयकर (तेन एमत्सकोमुनल इतकोमस्तस्काट) ;
 - (4) वृद्धावस्था पेंशन अंशदान (फोलपेंशनसविडग्रेन्ट) ;
 - (5) नाविक कर (समन्दसकातेन) ;
 - (6) विशेष आयकर (तेन सरलिज इतकोमस्तस्काट) ;
 - (7) चर्च कर (किरकेसकातेन) ;
 - (8) लाभांशों पर कर (उडवायतेसकातेन) ;
 - (9) रेल "पर डायम" निधि में अंशदान (विडराग तिल डया-पेनगेफोनडेन) ;
 - (10) हाइड्रोकार्बन कर (कुलब्रिनतेसकातेन) ;
 - (11) राज्य को देय पूंजी कर (पोरम्युस्कातेन तिल स्तातेन) ;
- (जिन्हें इसके बाद में "डेनिश कर" कहा जाएगा) ।

2. यह अधिनियम किसी भी समरूप अथवा भारत इसी तरह के करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान अधिनियम पर हस्ताक्षर होते की तारीख के पञ्चात् पञ्चाशक 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जायेंगे। संविदाकारी राज्यों के सज्ज प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अधिनियम में, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो ;

(क) "भारत" शब्द से भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है और उसमें राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र शामिल है और साथ ही साथ कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र, जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा श्रेयाधिकार हों ।

(ख) "डेनमार्क" शब्द से अभिप्रेत है डेनमार्क किंगडम का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है डेनमार्क का राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और साथ ही साथ उन भीमा तक कोई अन्य समुद्री क्षेत्र, जिसका नामकरण

अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किया गया हो अथवा इसके बाद डेनिश कानूनों के अनुसार किया जाए जहां डेनमार्क समरूपता संबंधों के अधिनियमों और उपरिर्कारी कानूनों में प्राकृतिक गंगाधारा के सम्बन्ध और अवशेषों के प्रयोजन, और अधिक अवशेष तथा सम्बन्धों के लिए अन्य कार्य-कलापों के संबंध में अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करता हो। इन शब्दों में फ़ैरो दीव समूह तथा ग्रीनलैंड शामिल नहीं होंगे ।

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों के विषयगत पाठ की ओरों के अनुसार भारत अथवा डेनमार्क अभिप्रेत है ;

(घ) "कर" शब्द से, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा डेनमार्क कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक अथवा भूल के संदर्भ में देय हो जिन पर यह अधिनियम लागू होता हो अथवा जो उन करों के संबंध में लगाया गया अर्थ-दंड हो ;

(ङ) "व्यक्ति" शब्द में व्यक्ति, कम्पनी और ऐसी कोई भी अन्य सत्ता शामिल है जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत कर लगने योग्य इकाई मानी जाती है ;

(च) "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसी निगमित निकाय अथवा कोई भी ऐसी सत्ता अभिप्रेत है, जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत कोई कम्पनी अथवा कोई निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है ;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(ज) "सज्ज प्राधिकारी" शब्दों से भारत के मामले में अभिप्रेत है, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; और डेनमार्क के मामले में अन्तर्देशीय राजस्व, रोमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(झ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जिसे किसी संविदाकारी राज्य को राष्ट्रियता प्राप्त हो और कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;

(ञ) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन जो किसी संविदाकारी राज्य द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अधिनियम के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, विषयगत में जब तक अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर यह अधिनियम लागू होता है ।

अनं चन्द्र .1

निव.सै०

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, "संविदाकारी राज्य का निर्यात" पर से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उनके अधिकारों, निवास, प्रवेश-स्थान अथवा इस प्रकार कि किसी अन्य कर्ता के कारण, वहाँ पर कर लगाया जा सकता है। परन्तु इस पर से यह व्यक्ति शामिल नहीं है, जिस पर उस राज्य में उसके व्यक्तियों से प्राप्त आय अथवा उगमों स्थित प्रजाति पर कर लगता है।

2. अज्ञा पैरासाफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई अर्थात् दोनों सदस्य-
कारों राज्यों का तत्त्वम् है, वहा उगर्क हैमिश्र तन्मत्त-तत्त्व तप यी
आपुर्ग :

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो। यदि उसे दोनों सदियोंकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हों, तो वह उसे सदियोंकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (सहव्यवस्थापन दिवों का संघ)।

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके सार्वभौमिक हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसकी किसी भी संविदाकारी राज्य से कोई ग्रांथी निताम उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निराग्री माना जाएगा जिसमें वह व्यावहारिक रूप से रहता हो ;

(ग) यदि वह व्यावहारिक रूप से दोनों ही राज्यों में रहता हो
अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह
उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह शक्तिशाली है।

(ए) यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा, उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के मुख्य प्राधिकारी, पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, पेशावाक । के उपयोगों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उग संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध स्थापित है :

मन्त्रः ५

स्वायं संस्थापन

1. इस अवसर पर के प्रयोजन के लिए "स्थायी स्थापना" पद से कार्यदार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ उद्यम का कार्यदार पूर्णतः अपना अंश दे दिया जाता है ।

2. "अज्ञानो मन्थापन" एव मे विशेषतः निम्नलिखित आशयः होतः :

(क) प्रदेश-व्यवस्था वा कोई स्थान .

(सू) कौटिल्य प्रामा.

$$(4) \quad \mathcal{A}(\frac{5}{2}) = \{1, 2, 3, 4\} \quad ;$$

(६) कर्म कायाना

(८) कर्त्तृ विज्ञापनम् ।

(न) काँई खान, तल प्रथवा तल वल मुआ, खदान प्रथवा प्राकृतिक संग्रामों के निष्कर्षण का काँई अल्य स्थान .

(६) कोई मान-गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरा के लिए भण्डारण करियाएँ मालिका रखता हो ;

(न) कोई फार्म, वगैरह प्रथवा अन्य स्थान अज्ञात, अन्यायपूर्ण अथवा गैरव्यवहारिक फार्म किंग जैत है ;

(अ) कोई पञ्चमर जिसका प्रचलन स्थित अथवा आदेश प्राप्त करने अथवा संगठन के लिए किया जाता हो ;

(अ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक समुदायों के खोख के लिए किया जाता है अर्थात् कि वे कार्यक्षमतापूर्वक निर्मा 12-माह के अवधि में एक अवधि अथवा 183 दिन के अवधि अथवा अधिक अवधियों के लिए किए जाते हैं ।

(८) कोई भवतःस्थित अथवा कोई निर्माण कार्य, प्रतिस्थापन अथवा संशोधन परियोजना अथवा उनसे संबन्धित प्रवेष्टा, कार्यक्षेत्रों, जहाँ ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यक्षेत्र (ऐसे स्थलों परियोजनाओं अथवा कार्यक्षेत्रों, यदि कोई हो के माध्यम से) १८३ दिन अथवा इससे अधिक समय के लिए जारी रहते हैं ;

उ. इस अतृच्छित के पूर्वार्थी उपबर्णों के होते हुए भी, 'स्वार्थी संख्या-पत' पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जा रहा है -

(क) किन्ती उद्यम के मान अवस्था पथ वस्तुओं के संयत भण्डारण अवस्था प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सविधाओं का प्रयोग ,

(ख) केशव भण्डारण शिव का प्रदर्शन के प्रथमनाथ उद्यम के माध्यम से पण्य वस्तुओं का स्टाक रखता।

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संगठित किए जाने के अतिरिक्त, उद्यम के माल म्रथवा पण्य करतुओं का स्टॉक रखना ,

(घ) किसी उद्यम के लिए मात्र श्रम तथा पद वस्तुओं का केवल व्यय करने श्रम या मूल्य एकत्र करने के पक्षधरों का रविवार का कोई निर्दिष्ट स्थान रखना ;

(ड) उद्यम के लिए अनन्य रूप से विश्वास प्राप्त वस्तु, गुणवत्ता प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ऐसे अन्य कार्यों के संबंध में जो प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, आश्रय का कोई निश्चित स्थान रखना ;

4 पैराग्राफ 1 तथा 2 के अन्तर्धी के होते हुए भी, यहाँ किसी स्वतंत्र हैमियत के अधिकारों, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य से दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर में जाने कर रहा है यहाँ उन उद्यम के प्रथम/वित्तियत राज्य में उस धिर्ज्ञ में एक स्थायी स्थापन होना मना जाता, यदि

(क) उसे उस राज्य में उसमें की ओर में अधिकारों सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह व्यावहारिक रूप में उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यक्षेत्र उस राज्य के विपरीत मान अथवा अन्य वस्तुओं अर्जित न करे, हो सम्पन्न हो

(ख) उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, परन्तु वह प्राचीन राज्य में व्यावहारिक रूप से मात्र अधिकार प्रयोगशुद्धों के अन्तर्गत रहता है। जिसमें से वह उस उद्देश्य के लिए और प्राचीनशुद्धों के नियमित रूप से किसी-किसी कारणों के लिए अधिकार है।

(ग) यह प्रयत्न किया गया था कि समस्त अथवा लगभग समस्त अथवा उद्यम के लिए अपना उन उद्यम के लिए तैयार अथवा उद्यमों के लिए जो उद्यमों को निर्यात करने हो उनके द्वारा निर्यात होता हो, अथवा उनके प्रकार के निर्यात के अंतर्गत हो, व्यावहारिक रूप से आदेश प्राप्त करता हो।

5. एक विश्वकारी राज्य के उद्देश का इंगित विश्वकारी राज्य में प्राप्त हम कारण कोई स्थिति सम्पादन होना नहीं पाता जाएगा कि वह हम अपने प्राप्ति में (हम) सम्पादन पूर्णता में है।

हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करना है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकाल पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उक्त उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से किए जाते हों जो उस उद्यम का नियंत्रित करते हों, उक्त उद्यम द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसी तरह के सामान्य नियंत्रण के अधीन हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अतिरिक्त के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

6. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती अथवा किसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे राज्य में (बड़े किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मान्य इस तथ्य में है, उक्त दोनों कम्पनियों में से किसी की कम्पनी को दूसरे की स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उक्त दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ यहाँ होगा जो उन संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिनमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोजन का अधिकार और खनिज भण्डार, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के खनन के लिए अधिकार कार्य करने के अधिकार से प्रतिकूल के रूप में परिवर्तनीय अथवा निर्यात अदायगियों के अधिकार। जलयान, नौकाएँ तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपबंध, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध, किसी उद्यम को अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उक्त राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उक्त राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके केवल उक्त अंश पर ही कर लगाया जा निम्नलिखित के कारण अपवाद होगा माना जा सकता है— (1) उक्त स्थायी संस्थापन (2) उक्त दूसरे राज्य में एक-समान अथवा उक्त मिलन-जुलते कार्य-कलाप अथवा पण्य वस्तुओं की विधि जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है; अथवा (3) उक्त दूसरे राज्य में कारोबार संबंधी किए जाने वाले एक-समान अन्य कार्य-कलाप अथवा उससे मिलन-जुलते कार्य-कलाप, जो उक्त स्थायी संस्थापन के माध्यम से किए जाते हैं।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलन-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलन-जुलते कार्य-कलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उक्त उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है। किसी भी हालत में जहाँ किसी स्थायी संस्थापन के कारण लाभों का सही राशि का निर्धारण करना प्रथम है अथवा उसके निर्धारण में असाधारण कठिनाइयाँ आती हैं जो स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों की गणना किसी उचित आधार पर की जाए।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उक्त अर्थों की कठिनाइयों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें छा उधार किए गए कार्य-काले तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे जो उक्त राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार हों और उतनी परिधि के अन्तर आते हों फिर चाहे वे उक्त राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित अथवा अन्यथा किए गए हों। किन्तु स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) को रायल्टियों, पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले फीसों अथवा ऐसी ही अन्य अदायगियों के तौर पर अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के तौर पर, अथवा किसी बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में यदि कोई रकम अदा की गई हो तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उक्त खसों का हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उनके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय के स्थायी संस्थापन द्वारा रायल्टियों, पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले फीसों अथवा ऐसी ही अन्य अदायगियों के रूप में की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) को प्रसारित की गई हो।

4. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में अनुभाजित किए जाने के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए लाभ आते वाले लाभों की तब करने की प्रथा रही है, वहाँ पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उक्त संविदाकारी राज्य को कर लगने वाले लाभों के ऐसी प्रथागत अनुभाजित-पद्धति से निर्धारण से प्रतिबंधित नहीं करेगी; लेकिन अपनाई गई अनुभाजित-पद्धति ऐसी होनी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ केवल एक कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उक्त स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्य वस्तुएँ खरीदी गई हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए लाभों को उक्त लाभों की तब तब अनुभाजित-पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उक्त सिद्धान्त चाहे ठीक तथा परोक्ष कारण नहीं हो।

7. जहाँ आय की मदों में लाभों की वे मंजूर शामिल हैं जिनका हक अधिसूचक के अन्य अनुच्छेदों में विवेचित किया गया है वहाँ उक्त अनुच्छेदों के अन्तर्गत उक्त लाभों को उक्त अनुच्छेदों के अन्तर्गत माना जाएगा।

अनुच्छेद 8

विमान परिवहन

1. किसी संविधानकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिवहन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पुल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध डेनिश, नार्वेजियन तथा स्वीडिश विमान परिवहन कर्माटियम, जिसे स्कैंडिनेवियन एयरलाइन्स पब्लिक (एन. ए. एन.) के रूप में जाना जाता है, द्वारा अर्जित लाभों पर लागू होंगे, परन्तु डेट डेनिश टेम्के लुफ्फाटलेनसलाब (डी. डी. एल.) स्कैंडिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम (ए. ए. एल.) के डेनिश भागीदार द्वारा धारित भाग में शेयरधारियों के अनुसूच उक्त लाभ के उर्थ भाग पर ही लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से संबंधित निधियों पर के व्याज को ऐसे विमान-परिवहन से प्राप्त लाभ माना जाएगा, तथा अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे व्याज के मामले में लागू नहीं होंगे।

5. "विमान-परिवहन" में तात्पर्य होगा—विमान के मालिकों या पट्टेदारी अथवा अवकाशाओं द्वारा विमान द्वारा यात्रियों, डाक, पण्यधन अथवा माल के परिवहन का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, विमान का आकस्मिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्ष संबंधित कोई अन्य कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 9

जहाजरानी

1. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान के प्रचालन से अर्जित लाभ उस संविधानकारी राज्य में ही कर योग्य होंगे, जिसमें उद्यम के प्रबंध का स्थान स्थित है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, ऐसे लाभों पर अन्य संविधानकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें जहाजों का प्राप्त किया जाता है, बशर्ते कि ऐसा प्रभावित कर:

(क) इस अभिसमय के लागू होने के बाद प्रथम पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 50 प्रतिशत, और

(ख) अनुषंगी पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 25 प्रतिशत; कर से अधिक नहीं होगा जो अथवा उस राज्य के आकस्मिक कानून द्वारा लगाया गया हो। बाढ़ में, पैराग्राफ 1 के उपबंध ही लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पुल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन अभिकरण में, जो जलयानों के प्रचालन में रत है, भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के प्रचालन से संबंधित निधियों पर व्याज को ऐसे जलयानों के प्रचालन से प्राप्त आय के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे, और

(ख) जलयान के प्रचालन से प्राप्त लाभों में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य वस्तुओं के परिवहन के संबंध में कटेतरों (जिनमें कटेतरों के परिवहन के लिए ट्रेकर तथा तत्संबंधी साज-सामान शामिल है) के इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किराए का भुगतान तथा व्याज शामिल है।

अनुच्छेद 10

नहरों की उद्यम

जहां:

(क) एक संविधानकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविधानकारी राज्य के किसी उद्यम को प्रबंध-व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूर्ण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविधानकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविधानकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध-व्यवस्था नियंत्रण या पूर्ण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के तहत होने की स्थिति में उन उद्यमों से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होना, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उन उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया सकेगा।

2. जहां कोई संविधानकारी राज्य अपने लाभों को उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में शामिल करता है और उस लाभों पर तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविधानकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और शामिल किए गए इस प्रकार के लाभ से लाभ हैं जो प्रयोज्यलिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त हुए हैं, यदि दो उद्यमों के बीच रखी गई शर्तें नहीं थीं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी गई होतीं, तो वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उस राज्य में लगाए गए कर की राशि का उचित समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का निर्धारण करने समय इस अभिसमय के अन्य उपबंधों की ओर भी ध्यान देना होगा और संविधानकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों को, यदि आवश्यक हुआ, एक-दूसरे से परामर्श करना होगा।

अनुच्छेद 11

लाभों का

1. एक संविधानकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविधानकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे लाभों पर उस संविधानकारी राज्य में भी कर लग सकता है जिस राज्य की लाभों अदा करने वाली कम्पनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

(क) लाभों की प्राप्त रकम का 15 प्रतिशत, यदि हितभागी स्वामी कोई ऐसा कम्पनी है, जो लाभों अदा करने वाली कम्पनी के रूप में कम 15 प्रतिशत शेयरों का स्वामी है;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभों का राकत रकम का 25 प्रतिशत संविधानकारी राज्यों के गद्यम प्राधिकारियों को इस सीमाओं को लागू करने का तरीका अपनी सख्तियों में निपटारा जाएगा। यह पैराग्राफ ऐसे लाभों के मामले में कम्पनी के कराधान को प्रभावित करता होगा जिनमें से जलयानों का परिवहन शामिल है।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" पद का अर्थ है जेयों से प्रथम अथवा अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण-दाय नहीं हों, लाभों में सम्मिलित हों, तथा अन्य निर्गमित अधिकारों में प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयर से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभों का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभों अदा करने वाली कम्पनी निवासी हो, उसमें स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से उसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ करता हो और वह सम्पत्ति, जिसके संबंध में लाभों अदा किए जाते हैं, वह इस प्रकार की स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रक्षारण रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में यथा स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है और वह दूसरे संविदाकारी राज्य में लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरा राज्य कम्पनी अदा किए गए लाभों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहाँ तक कि उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को इस प्रकार के लाभों अदा नहीं किए जाते अथवा जहाँ तक कि वह स्थिति जिसके संबंध में लाभों अदा किए जाते हैं, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन से अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रक्षारण रूप से सम्बद्ध नहीं है अथवा कम्पनी के अतिरिक्त लाभों पर लगाया जा सकने वाला कर नहीं लगाया जाएगा जहाँ तक कि लाभों अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद 12

व्याज

1. अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 4 के उपबन्ध और अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न व्याज को यदि दूसरे संविदाकारी राज्य किसी निवासी को अदा किया जाता है, तो उस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसमें यह उत्पन्न होता है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार होगा। परन्तु, इस अभिसमय के लागू होने की तारीख के बाद दिए गए ऋण अथवा भूजित कर्ज के सम्बन्ध में देय व्याज पर ऐसा प्रभावित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

(क) सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि ऐग, व्याज किसी बैंक द्वारा मंजूर किए गए किसी प्रकार के किसी ऋण पर अदा किया जाता है, और

(ख) सभी अन्य मामलों में सकल राशि का 15 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होने हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले व्याज पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में वह से छूट प्राप्त होगी वहाँ कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा, उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, उसके सहायकारी राज्य के केंद्रीय बैंक अथवा उस सरकार के किसी प्रतिनिधित्व अथवा उस निवासी के ऐसे ऋण सेवा के बारे में उस दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी फर्म निवासी द्वारा, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण, उस दूसरे संविदाकारी राज्य के केंद्रीय बैंक अथवा उस सरकार को किसी एजेंसी द्वारा वित्त-प्राप्त, गारंटी अथवा जीमांकित किया गया है, प्राप्त किया जाता है।

1. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्याज" शब्द में अभिप्रेत है—
प्रत्येक प्रकार के ऋण-दायों से प्राप्त, आय सहित वह प्रत्येक ऋण प्रतिभूत की अथवा नहीं और चाहे कर्जदार के लाभों में भाग लेने का अधिकार रखता हो या नहीं और आम तौर पर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय तथा बंधनों या ऋण पत्रों में प्राप्त आय, जिसमें ऐसे प्रतिभूतियों, बंध पत्रों या ऋणपत्रों में सम्बद्ध प्रीमियम तथा पुरस्कार शामिल हैं। जिसमें से कोई भी अदायगों के लिए वाणिज्य-प्रसारों की इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए व्याज नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने में, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जहाँ व्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ निष्पादन करता हो तथा जिन ऋण-दायों के संबंध में व्याज अदा किया जाता हो वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रक्षारण रूप से सम्बन्धित हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध, जहाँ भी लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज उत्पन्न हुआ तब माना जाएगा यदि व्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-भाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति को, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गई है, तथा ऐग, व्याज उस स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गई है, तथा ऐग, व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा अथवा निश्चित स्थान द्वारा वित्त किया जाता है, तब ऐग, व्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ व्याज अदा करने वाले तथा हितभागी स्थायी के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के कारण, अदा की गई व्याज का रकम, उस ऋण-दाय को छूटने में रखने हुए जिनके लिए व्याज को रकम अदा की गई है, किन्तु भी कारण उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्थायी के बीच सहमति है। गई होगी, यहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। इस प्रकार के मामले में, अदायगी की रकम के अतिरिक्त आय पर, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों का सम्बन्ध अनुगत करने हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य को कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

राज्यनिधियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फंड

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई राजनिधियों तथा दूसरे तकनीकी सेवाओं के लिए फंड पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे राजनिधियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फंड पर उस संविदाकारी राज्य में जो उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है, जिसमें वह उत्पन्न होती है। लेकिन यदि प्राप्तता राजनिधियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फंड का लाभकारी स्वामी हो, तो इस प्रकार लगाया कर राजनिधियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फंड के लिए वाणिज्य-प्रसारों के लिए प्रेषित किया जा सकता है।

3. इस अनुच्छेद में क्या-प्रयुक्त "राष्ट्रियता" शब्द के तात्पर्य किसी भी प्रकार की ऐसी अदायगियों से है, जो सांस्कृतिक कलात्मक, अथवा वैवाहिक रीतियों, जिसमें वनविश्व, जिनमें या रीतियों यथा इच्छा पर प्रत्याग के लिए प्रदान की जाते हैं, या अन्य शक्ति है, को, वेदांग, देश भाई, विवाह अथवा माता-पिता-पुत्र-पुत्री यथा स्त्रियाँ के किसी भी किसी राष्ट्र के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण से प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव में संबंधित सूचना के लिए प्रतिकूल के रूप में प्राप्त हो।

4. इस अनुच्छेद में क्या-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" शब्द से प्रत्यक्षतः तकनीकी अथवा परामर्शदाता स्वरूप की सेवाओं के प्रतिकूल में, जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कामकाज की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, छायायगियों करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की गई अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को की गई किसी भी रकम की छायायगियाँ अभिप्रेत हैं।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध इस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि राष्ट्रियता अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें राष्ट्रियता अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, उसमें स्थित किसी स्वामी सम्पत्ति के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उसे दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत संचालन निष्पादित करता है तथा यह अधिकार सम्पत्ति, अथवा संविदा, जिसके माध्यम से राष्ट्रियता अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, ऐसे स्वामी सम्पत्ति अथवा निश्चित स्थान से प्रसारित कर से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उद्देश्य और भाव सामान्य हो लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में राष्ट्रियता तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस इस स्थिति में उद्भूत हुई मानी जाएगी, यदि अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निकाय हो। परन्तु, जहाँ राष्ट्रियता अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी सम्पत्ति अथवा निश्चित स्थान हो जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रियता अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की दायिरी उत्पन्न हुई हो, तथा जहाँ राष्ट्रियता अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्वामी सम्पत्ति अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है, तब ऐसी राष्ट्रियता अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें उक्त स्वामी सम्पत्ति अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ अदा करने वाले तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विवाद सम्बन्ध होने के कारण राष्ट्रियता अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गई फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐसे संबंधों के लक्ष्य होने की स्थिति में अदा की गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अंतिम चरित्त रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों की रकम का प्रतिशित भाग इस अनुच्छेद के अन्य उपबन्धों का सम्पर्क धारण करने हुए प्रयोग संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाने योग्य रहेगा।

अनुच्छेद 11

पूँजीगत अभिलाष

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाषों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. इन सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त हुए अभिलाषों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी सम्पत्ति की व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की स्वतंत्र व्यक्तिगत संपत्ति के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी निश्चित स्थान में सम्बन्धित अचल सम्पत्ति हो, जिसमें ऐसे स्वामी सम्पत्ति (अर्थात् अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तर्गत से होने वाले ऐसे अभिलाष भी शामिल हैं, उन पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय वातावरण में अथवा जहाँ अचल सम्पत्तियों अथवा वायुमार्गों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुमार्गों के संचालन से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त अभिलाषों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकारी निवासी है।

4. डैनिश, स्वीडिश और नार्वेजियन वायु परिवहन कम्पनियों में डैनिशियन एयरलाइन्स सिस्टम (एम. ए. एम.) द्वारा अर्जित लाभों के सम्बन्ध में इस पैराग्राफ के उपबन्ध ऐसे लाभों के केवल उन समानुपात में ही लागू होंगे जो कि दैनिक एयरलाइन्स सिस्टम (डी. डी. एम.) स्वीडिशियन एयरलाइन्स सिस्टम के डैनिश सहभागी द्वारा उस कम्पनियन में धारित की हुई सहभागिता के अनुसूप हों।

किसी ऐसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तर्गत से प्राप्त अभिलाषों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

6. किसी ऐसी कम्पनी के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अन्तर्गत से प्राप्त अभिलाषों पर, जो कंपनी किसी संविदाकारी राज्य की निवासी हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा बशर्ते कि ऐसे शेयरों की रकम उस कम्पनी की शेयर पूँजी की कम से कम 10 प्रतिशत हो।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त अभिलाषों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकारी निवासी है।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी स्वतंत्र के अन्य स्वतंत्र कार्यालयों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में करणीय होगी।

(क) यदि उसे अपने कार्यालयों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में उसकी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है, अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उतरने की उसकी अवधि अथवा अवधि उस दूसरे राज्य के विनियम वर्ष में 183 दिन अथवा कम मिलाकर उसमें अधिक होती है, उस मामले में, उक्त आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में निष्पादित उसके कार्यालयों से प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पर में विशेष कर से स्वतन्त्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, भौतिक अथवा प्रस्थापन संबंधी कार्यान्वयन तथा चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाओं के स्वतन्त्र कार्यान्वयन शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

प्राप्तिव्यवस्थित सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19 और 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, गभूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिवारिक परबन्धन उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उसका निवेदन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं हो। यदि इस प्रकार निवेदन किया जाता है तो ऐसे पारिवारिक पर, तो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में ही लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिवारिक पर कोशन प्रयोजनविहित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि:

- (क) प्राप्तकर्ता उस दूसरे राज्य के वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन से कमविक की अवधि अथवा अवधियों के लिए, उस दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो, तथा
- (ख) पारिवारिक किसी ऐसे नियोजन द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
- (ग) पारिवारिक, किसी ऐसे स्थायी संगठन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहुत दूर भिन्न भिन्न हो, जो नियोजन का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्वर्ती उपबन्धों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्योग द्वारा अन्तरराष्ट्रीय वातावरण में जनमानस आवाहन के परिचालन में किए गए किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिवारिक कर उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

4. जहां उनका कोई भी निवासी रजिस्ट्रेशन परतन हस्त मिश्रण (एम. ए. ए.) कम्प्यूटिंग द्वारा अन्तरराष्ट्रीय वातावरण में किसी वायुयान के परिचालन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में पारिवारिक प्राप्त करता है तो ऐसे पारिवारिक पर कर केवल उनका ही में ही लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 17

निदेशकों की फीस तथा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण अधिकारियों का पारिवारिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक मण्डल के एक सदस्य की हैमियन से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा उसके मिशन-जुलसी अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी ऐसी कम्पनी के, जो दूसरे राज्य की निवासी है, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पर पर नियुक्त समेकाई की हैमियन में प्राप्त वेतन मजदूरी तथा उगमे मिशन-जुलसी पारिवारिक उस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-18

मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबन्धों के होने हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में भिन्न एक भिन्नतर व्यक्ति योग्य अथवा दूरदर्शन के माध्यम से अथवा अन्य संवित्कार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में अपने व्यावसायिक कार्यान्वयनों से जिन्हें वह दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न करता है, प्राप्त आय पर कर उस दूसरे राज्य में लगा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा इस प्रकार की अपनी हैमियन में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यान्वयनों के संबंध में उद्भूत होने वाली आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां अनुच्छेद 17, 18 और 16 के उपबन्धों के होने हुए भी उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा, जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यान्वयन किए गए हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होने हुए भी किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैमियन में किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यान्वयनों से अतिरिक्त आय प्रयोजनविहित संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यान्वयनों प्रयोजनविहित संविदाकारी राज्य की, जिसमें उसके राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजनिक विधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त समर्थित होते हैं।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 2, 15 और 16 के उपबन्धों के होने हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैमियन में एक संविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यान्वयनों के संबंध में प्राप्त आय, मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी स्वयं को प्राप्त नहीं होती है परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि वह दूसरा व्यक्ति दूसरे राज्य की, जिसमें उसके राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजनिक विधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त समर्थित किया गया हो।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा के सम्बन्ध में पारिवारिक तथा वेतन

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के निमित्त प्रदान वेतन में भिन्न पारिवारिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।

(ख) लेकिन ऐसे पारिवारिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो

(i) उस राज्य का नागरिक है अथवा;

(ii) भव सेवाएं देने के प्रयोजनसे उस राज्य का निवासी नहीं बना था।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा सृजन किए गए कोष में से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदान किसी वेतन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।

3. अनुच्छेद 16 और 17 के उपबन्ध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारोबार के मिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर लागू होंगी।

अनुच्छेद 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का देश करने के तुरन्त पहले संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, निम्नलिखित पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

(क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उने की गई अदायगियाँ; और

(ख) उस दूसरे राज्य के किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक, जो 20000 डैनिश आउन अथवा भारतीय मुद्रा में इसके समकक्ष से अधिक न हो, बणर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः उसके अध्ययन से संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।

2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा जो शिक्षा अथवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्यक्ति को किसी भी हालत में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुँचने की तारीख से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 21

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के अर्थात् रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की उन मर्यादों पर कर जहाँ कहीं ये उद्भूत होती हों, अतएव इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा — परिभाषित अवल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में, वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएँ निष्पादित करता है, तथा ऐसी अधिकार अथवा सम्पत्ति जिनके सम्बन्ध में ऐसी आय अथवा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप में सम्बन्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्यादों पर भी, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेद में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 22

पूजी

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अवल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूजी पर जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामित्व में हो तथा परे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूजी पर, जो किसी ऐसे स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के रूप में है, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, निरूपित पूजी पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों और वायुयानों द्वारा तथा आन्तरिक जलतरंग परिवहन में रत मोटर नौकाओं द्वारा और ऐसे जलयानों, वायुयानों, और मोटर नौकाओं के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूजी पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, जिसमें उद्यम निवासी है।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूजी के अन्य सभी तत्वों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान का परिहार

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवक्त कानून अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में, आय और पूजी के कराधान के मामले में लागू रहेंगे जब तक कि इस अतिमय में उनके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाता है।

2. भारत के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्न प्रकार से किया जाएगा।

(क) जहाँ भारत का कोई निवासी इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार आय प्राप्त करता है अथवा पूजी का स्वामित्व रखता है, तो उस पर डेनमार्क में कर लगाया जा सकता है, वहाँ भारत उस निवासी की आय पर उस रकम के बराबर कर से कटौती के रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती द्वारा छूट देगा जो डेनमार्क में भरा किए गए आय कर की रकम के बराबर हो; और उस निवासी की पूजी पर कर से कटौती के रूप में उतनी रकम पर छूट प्राप्त होगी जो डेनमार्क में अथवा किए गए पूजी कर की रकम के बराबर हो। तथापि, दोनों मामलों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती (कटौती दिए जाने से पूर्व यथा संगणित) आयकर अथवा पूजी कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय अथवा पूजी, जैसा भी मामला हो, के कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता हो जिस पर डेनमार्क में कर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जहाँ ऐसा निवासी कोई ऐसी कम्पनी है जिसके द्वारा भारत में अतिरिक्त वेप है, वहाँ डेनमार्क में भरा किए गए आयकर के बारे में कटौती प्रथमतः कम्पनी द्वारा भारत में देय आयकर से की जाएंगी और शेष के लिए, यदि कोई हो, भारत में उसके द्वारा देय अतिरिक्त से कटौती की अनुमति दी जाएगी।

(ख) जहाँ भारत का कोई निवासी इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार आय प्राप्त करता है अथवा पूजी का स्वामित्व रखता है, तो उस पर डेनमार्क में ही कर लगेगा, वहाँ भारत

उस कर आधार में यह आय अथवा पूंजी शामिल कर सकता है परन्तु आयकर अथवा पूंजी कर से कटौती के रूप में उतनी रकम की अनुमति देगा जो डेनमार्क में प्राप्त आय से अथवा पूंजी के स्वामित्व से जैसा भी मांगता हो, प्राप्त आयकर अथवा पूंजी कर का भाग है।

3. डेनमार्क के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्न प्रकार से होगा :

(क) उप पैराग्राफ (ग) के उपबंधों के अधीन, जहाँ डेनमार्क का कोई निवासी इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार आय प्राप्त करता है अथवा पूंजी का स्वामित्व रखता है, तो उस पर भारत में कर लगाया जा सकता है, वहाँ डेनमार्क निम्नानुसार अनुमति देगा—

(i) उस निवासी की आय पर कर में उतनी रकम की कटौती दी जाएगी, जो भारत में अदा किए गए आयकर के बराबर हो ;

(ii) उस निवासी की पूंजी पर कर से उतनी रकम की कटौती दी जाएगी जो भारत में अदा किए गए पूंजी कर के बराबर हो ;

(ख) तथापि, उक्त दोनों मामलों में से किसी भी मामले में, इस कटौती की रकम कटौती दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित आयकर अथवा पूंजी कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो भारत में कर लगाई जा सकने वाली आय अथवा पूंजी के कारण, जैसा भी मामला हो, प्राप्त होती हो ;

(ग) जहाँ डेनमार्क का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूंजी का स्वामित्व रखता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार केवल भारत में ही कर लगाया जा सकेगा वहाँ डेनमार्क इस आय अथवा पूंजी को कर आधार में शामिल कर सकता है परन्तु वह आयकर अथवा पूंजी कर के उस अंश पर आयकर अथवा पूंजी कर से छूट की अनुमति देगा, जो भारत में प्राप्त होने वाली आय अथवा भारत में स्वामित्व वाली पूंजी के कारण, जैसा भी मामला हो, प्राप्त होगा है ;

(घ) उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित कटौती के प्रयोजनार्थ "भारत" में अदा किया गया आयकर" पद में, भारत के कानूनों के अन्तर्गत और इस अभिसमय के अनुसार, निम्नलिखित के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए मंजूर की गई कर की किसी छूट अथवा कटौती को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामिल हुई मानी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में देय हुई हो :

(i) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4), 10(4क), 10(4ख), 10(6), (vi)(क), 10(15)(iv), 10क, 32क, 80अ, 80आ, 80-अ और 80-ड, जहाँ तक कि वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर

किए जाने की तारीख को लागू थी और तब से उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है अथवा उसमें केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ; अथवा

(ii) कोई भी अन्य उपबन्ध जो कर योग्य आय अथवा कर में किसी छूट अथवा कटौती की संगणना करने में कटौती मंजूर करते हुए इसके बाद अधिनियमित किया गया हो जिसको संबिदाकारी राज्यों के सख्त अधिकारों भारत के अधिकारों के प्रयोजन के लिए होना मानते हों, यदि उसमें उसके बाद संशोधन नहीं किया गया हो, अथवा उसमें केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो :

(ङ) उप पैराग्राफ (क) में उल्लिखित कटौती के प्रयोजनार्थ, व्याज, रायल्टियाँ तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर भारतीय कर किसी भी हालत में निम्नलिखित से कम दर पर संवत् किये गये रूप में नहीं समझा जाएगा :

(i) व्याज के मामले में—

(क) बैंक के मामले में 10 प्रतिशत; और

(ख) अन्य मामले में 10 प्रतिशत; और

(ii) रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के मामले में 20 प्रतिशत।

अनुच्छेद 24

सम-व्यवहार

1. एक संबिदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संबिदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान-व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और उससे सम्बन्धित अपेक्षाओं से निम्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो जा उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर समान परिस्थितियों तथा समान स्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संबिदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संबिदाकारी राज्य में किसी न्याया संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में समान परिस्थितियों में और समान शर्तों के अधीन कार्यक्षेत्रों में उक्त किसी उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अन्तर्गत हो।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं समझा जाएगा कि एक संबिदाकारी राज्य ऐसे मामलों को, जो उस राज्य के

निवासी नहीं है, कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व छूटें, राहतें, कटौतियाँ और कटौतियाँ प्रदान करने का बाध्य होगा जो कानूनन केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध है, जो वहाँ के निवासी हैं।

4. जिन मामलों में अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं उन्हें छोड़कर एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया व्याज, राशियाँ और अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कर लम्बे योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं समान शर्तों के अधीन कटौती पाने योग्य होंगे, जैसे कि वे प्रथमोत्प्लवित राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए थे। इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को किए गए कोई कृण ऐसे उद्यम को कर लगने योग्य पूँजी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन्हीं समान शर्तों के अधीन कटौती पाने योग्य होंगे जैसा कि वे प्रथमोत्प्लवित राज्य के किसी निवासी को अनुबंधित किए गए थे।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनको पूँजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों को, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोत्प्लवित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसा अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं ने मिल अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोत्प्लवित संविदाकारी राज्य में अन्य समान उद्यमों पर समान परिस्थितियों में और समान शर्तों के अधीन लागू है अथवा हो सकती है।

6. इस अनुच्छेद में "कराधान" पत्र में वे कर अभिप्रेत हैं जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी वह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उन पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के आन्तरिक कानूनों द्वारा उपबन्धित उपायों के होते हुए भी, अपना मामला उन संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है। यह मामला उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे ऐसा कराधान उद्भूत होता है, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी सम्पोजनक हल पर पहुँचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे

कराधान के निवारण की पुष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय का व्याख्या करने अथवा उसे लागू करने में यदि कोई कठिनाईयाँ अथवा भ्रंश उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक समझौते से हल करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श भी कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुँचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं) आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों के अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से सम्बन्धित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस अभिसमय के अन्तर्गत आते हैं, जहाँ तक कि उनके मधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी अथवा अपवर्धन को रोकने के लिए अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन, यदि उक्त सूचना को, सूचना भेजने वाले राज्य में गुप्त रूप से गुप्त समझा जाता है, जो तो उस केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा उनकी यथार्थ उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित प्रयोगों के निर्धारण में अन्तर्गृह्य हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे उक्त सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा, जिसमें, जहाँ कहीं उपयुक्त हो, कर के परिहार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नती तौर पर किया जाएगा अथवा किसी मामले विशेष के संदर्भ में अनुरोध के

आधार पर अथवा दोनों तरह से किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सभ्य प्राधिकारी नेनी पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची पर समय समय पर अपनी सहमति व्यक्त करे।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ के पद्यों का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित उत्तरदायित्व डाला जाए।

(क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्राशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्राशासनिक सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं ;

(ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिससे कोई व्यापारिक व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी, गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 27

बसूली में संयोग

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय से संबंधित करों की बसूली में उन मामलों में एक दूसरे राज्य की मदद करने और समर्थन देने का जिम्मा लेते हैं, जहां अनुसूचक राज्य के कानूनों के अनुसार, कर निश्चित रूप से देय है।

2. प्रवर्तन अथवा बसूली के किसी अनुसूचक के मामले में किसी भी संविदाकारी राज्य के कर सम्बन्धी दावों को, जिनका अन्तिम रूप से पता लगाया जा चुका है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्रवर्तन के लिए स्वीकार किया जाएगा जिससे अनुसूचक किया गया है, और उनकी बसूली उस राज्य के करों के प्रवर्तन और उनकी बसूली हेतु लागू कानूनों में की जाएगी।

3. भारतीय कर के मामले में अनुसूचक पक्ष को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा डेनिश टेक्स डायरेक्टोरेट, स्टार्टशाटडेडायरेक्टोरेट पोस्ट बॉक्स 100, डी. के. - 3460 बिरकेराड, डेनमार्क के मास भेजा जाएगा, और उसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न होगा जिससे कि भारत के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करों का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और वे करदाता द्वारा देय हैं।

4. डेनिश कर के मामले में अनुसूचक पक्ष डेनिश टेक्स डायरेक्टोरेट द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (जि. कर. प्र.) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जाएगा और उसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न होगा जिससे कि डेनमार्क के कानूनों में

यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करों का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और वे करदाता द्वारा देय हैं।

5. जहां कर सम्बन्धी दावा उभर सम्बन्ध में अर्पित किए जाने अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण निर्णायक नहीं बना हो, वहां एक संविदाकारी राज्य, अपने राजस्व को बचाने के लिए, दूसरे संविदाकारी राज्य से उसके बारे में ऐसे अंतरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उभर दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत इस तरह वैध है।

6. किसी करदाता से प्राप्त करों की बसूली में सहायता के लिए अनुसूचक पक्ष तभी पेश किया जाएगा जब अनुसूचक करने वाले संविदाकारी राज्य में उस करदाता से कर बसूल करने के लिए उसकी पर्याप्त परिस्थितियां उपलब्ध न हों।

7. जिस संविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 5 के अनुसरण में कर बसूल किया जाता है, वह राज्य इस प्रकार बसूल की गई रकम को तत्पश्चात् तुरन्त दूसरे संविदाकारी राज्य को भेजेगा, जिसने अनुसूचक किया था, परन्तु ऐसे कर की बसूली में सहायता किए जाने के दौरान कोई आवश्यक लागत को, यदि कोई हो, दोनों राज्यों के सभ्य प्राधिकारियों के बीच आपास में सहमत हुई सीमा तक वापिस करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 28

राजनयिक एजेंट और काउंसिलों अधिकारी

इस अभिसमय की किसी भी बात से राजनयिक एजेंट का काउंसिलों अधिकारियों पर अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 29

क्षेत्रीय विस्तार

1. इस अभिसमय का विस्तार या तो इनका सम्पूर्णतः में या ऐसे परिवर्तनों सहित सामान्य करार द्वारा किया जा सकता है, जिनके लिए डेनमार्क के खेल के किसी भाग के लिए सहमति हुई है और जिसे अभिसमय के प्रवर्तन से विभिन्न रूप से बाहर रखा गया है और जिससे ऐसे स्वतंत्र वाले समान कर पर्याप्तता लगाए जाते हैं, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है। ऐसा कोई विस्तार उस तारीख से और अभिसमय के पर्यवसान की शर्तों सहित, ऐसे परिवर्तनों और शर्तों के अधीन प्रभावी होगा, जैसे कि राजनयिक माध्यमों के जरिए आदान-प्रदान की उभर वाली टिप्पणियों में संविदाकारी राज्यों के बीच अथवा उनकी मासिक कार्यविधियों के अनुसार किसी भी अन्य पद्धति में निर्दिष्ट अन्तर्गत है।

2. जब तक दोनों संविदाकारी राज्यों में अन्त्यष्टा महमति न हो, तब तक डेनमार्क के क्षेत्र के किसी भाग के लिए, जिसे इस अनुच्छेद के अन्तर्गत बढ़ाया गया है, इस अभिसमय का प्रवर्तन अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत दोनों राज्यों में से किसी एक के द्वारा अभिसमय का समापन भी, उस अनुच्छेद में दी गई व्यवस्था के अनुसार होगा।

पाठों में से किसी भी पाठ के बीच भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

ह.

ह.

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

डेनमार्क किंगडम की सरकार की ओर से

अनुच्छेद 30

प्रवर्तन

1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगी कि इस अभिसमय के प्रवर्तन के लिए सांविधिक अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

2. यह अभिसमय पैराग्राफ-1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से परवर्ती अधिसूचना की तारीख को प्रवर्तित होगा और इसके उपबन्ध उस वर्ष से जिसमें पैराग्राफों में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से परवर्ती अधिसूचना दी गई हो अगले कलेंडर वर्ष में बिनाक 1 जनवरी को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले आय वर्ष के लिए कर के संबंध में प्रभावी होगी।

3. आय के बोहरे कराधान के परिहार के संबंध में 16 सितम्बर, 1959 को कोपेनहेगन में भारत और डेनमार्क की सरकारों के बीच हस्ताक्षर किया गया करार उस समय निष्प्रभावी हो जाएगा, जब इस अभिसमय के उपबन्ध पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रभावी होगी।

अनुच्छेद 31

पर्यवसान

यह अभिसमय तब तक लागू रहेगा, जब तक दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता है। दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय को उस वर्ष से, जिस वर्ष में यह अभिसमय लागू हुआ है, पांच वर्षों की अवधि के बाद के किसी कलेंडर वर्ष के जून के 30वें दिन को अथवा उससे पहले राजनयिक माध्यमों से दायी समाप्ति का लिखित नोटिस देकर समाप्त कर सकेगा। ऐसी स्थिति में, यह अभिसमय, उस वर्ष जिसमें उक्त अधिसूचना दी जाती है, के परवर्ती कलेंडर वर्ष एक जनवरी को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले आय वर्ष अथवा परवर्ती आय वर्षों के संबंध में कर के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकारीयों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं।

कोपनहेगन में वर्ष एक हजार नौ सौ नवासी के मार्च माह के आठवें दिन को, हिन्दी, डेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया। इसके सभी पाठ, समानतः प्रामाणिक हैं। इन

प्रतीकों

भारत सरकार और डेनमार्क किंगडम की सरकार ने:

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व प्रवर्धन को रोपने के लिए इस अभिसमय को सम्पन्न करने हुए:

उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के समय निम्नलिखित उपबन्ध के संबंध में सहमति व्यक्त की है, जो उसके अतिरिक्त अंग्रेजी में होगी:

(1) अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 3(क) के प्रयोजनार्थ, यह समझा जाता है कि उसमें निर्दिष्ट कर की दरें किसी भी हालत में भारतीय कर कानूनों के अन्तर्गत आय की ऐसी श्रेणियों पर लागू होने वाले प्रतिबंधकारी कर की दर से अधिक नहीं होंगी।

(2) अनुच्छेद 27 के प्रयोजनार्थ, करदाता से प्राप्य करों की वसूली में सहायता के लिए अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे कर 2000 डेनिश क्राउन अथवा भारतीय मुद्रा में उनके समतुल्य अथवा उससे अधिक नहीं हो जाते।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रतीकों पर हस्ताक्षर किये हैं।

कोपनहेगन में वर्ष एक हजार नौ सौ नवासी के मार्च माह के आठवें दिन को हिन्दी, डेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया। इसके सभी पाठ प्रामाणिक हैं। तीन पाठों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

ह.

ह.

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

डेनमार्क किंगडम की सरकार की ओर से

प्रतीकों

भारत गणराज्य की सरकार और डेनमार्क किंगडम की सरकार ने आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार

तथा राजस्व अपव्ययन को रोकने के लिए इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर करते समय हस्ताक्षरकों ने यह गठमति व्यक्त की है कि निम्नलिखित उपबन्ध इस अधिसूचना के अधिनियम अंतर्गत हैं:—

1. यह अधिसूचना फ़ैरी द्वीप समूह के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू किया गया है।

2. अधिसूचना में, "डेनमार्क किंगडम" और "डेनमार्क" शब्द फ़ैरी-द्वीप समूह पर भी लागू होंगे, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

3. इस वर्तमान प्रोटोकॉल के अनुसरण में ऐसे करों में, जो अधिसूचना के विषय हैं, निम्नलिखित कर भी शामिल होंगे जो फ़ैरी द्वीप समूह पर लगाए जाते हैं:

- (क) स्टैट मिल सैण्डसकारेन (प्रारंभिक आयकर);
- (ख) कॉम्पुतस इण्डकोसत्सकैट (सामवायिक आयकर);
- (ग) फ़िरकेत्सकैट (चर्च कर);
- (घ) उडनायनेत्सकैट (लाभांश पर कर);
- (ङ) एजेंडोमस्वानसंगिफ्ट (वास्तविक सम्पदा से प्राप्त होने वाले लाभ पर कर);
- (च) रायलटियाफ़गिफ्ट (रायल्टी पर कर);

4. "सक्षम प्राधिकारी" शब्द में अर्थ है—फ़ैरी द्वीप समूह के मामले में फ़ैरी स्थानीय सरकार अथवा अधिसूचना के संदर्भ में प्रश्नों को हल करने के लिए ऐसा प्राधिकरण, जिसे स्थानीय सरकार की ओर से प्राधिकृत किया गया है।

5. यह प्रोटोकॉल उस तारीख से लागू होगा तथा प्रभावी होगा जिस तारीख से अधिसूचना लागू होगी।

जिनके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् पाधिकृत अधिकृत अधिकारियों ने इस वर्तमान प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

6. कोपनहेगन में एक हजार तीसरी वर्षा के माचं मास के आठवें दिन हिन्दी, डेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में संपन्न किया गया। इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। इन पाठों में से किसी भी पाठ के बीच भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

ह.

ह.

र. च. शुक्ला
भारत गणराज्य की
सरकार का और से

जेम्स रोज़मन
डेनमार्क किंगडम की
सरकार का और से

[क्र.सं. 505/3/81-एफ.टी.डी.]

अधिसूचना सं. 8460

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th September, 1989

INCOME-TAX

G.S.R. 853 (E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has come into force on the 13th day of June, 1989, on the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the constitutional requirements, as required by paragraph 1 of Article 30 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (13 of 1961), section 24A of the Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

"ANNEXURE CONVENTION

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE KINGDOM OF DENMARK

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark;

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital;

Have agreed as follows :

Article 1 PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 TAXES COVERED

1. The taxes to which this Convention shall apply are :

(a) In India :

- (i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);
- (iii) the wealth-tax imposed under the Wealth-tax Act, 1957 (24 of 1957);

(hereinafter referred to as "Indian tax")

(b) In Denmark :

- (i) the income-tax to the State (indkomstskatten til staten);
- (ii) the municipal income-tax (den kommunale indkomstskat) ;
- (iii) the income-tax to the country municipalities (den amtskommunale indkomstskat);
- (iv) the old age pension contribution (folkepensionsbidraget) ;
- (v) the seamen's tax (sømandsskatten);
- (vi) the special income-tax (den særlige indkomstskat);
- (vii) the church tax (kirkeskatten);
- (viii) the tax on dividends (udbytteskatten);
- (ix) the contribution to the sickness "per diem" fund (bidrag til dagpengefonden);
- (x) the hydrocarbon tax (kulbrinteskatten);
- (xi) the capital tax to the state (formueskatten til staten);

(hereinafter referred to as "Danish tax").

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed

by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3 GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes territorial sea and the airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law;
- (b) the term "Denmark" means the territory of the Kingdom of Denmark including the territorial sea of Denmark and the airspace above it, as well as any other maritime area to the extent that that area in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of the seabed or its sub-soil and the superjacent waters and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the area; the term does not comprise the Faroe Islands and Greenland;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Denmark as the context requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Danish tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the terms "competent authority" means in the case of India, the Central Government Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Denmark, the Minister for Inland Revenue, Customs and Excise or his authorised representative;

(i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in a Contracting State;

(j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that state in respect only of income from sources in that state or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has permanent home available to him if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode ;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office ;

(d) a factory;

(e) a workshop ;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources ;

(g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others ;

- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (i) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (j) an installation or structure used for the exploration of natural resources provided that the activities are carried on for a period or periods of 183 days or more in any twelve-month period;
- (k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities if any) continue for a period of 183 days or more.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, or the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for other activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and right to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for

management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply to profits derived by the Danish, Norwegian and Swedish air transport consortium, known as the Scandinavian Airlines System (SAS), but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in the consortium held by Det Danske Luftfartsselskab (DDL), the Danish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

4. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

5. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9 SHIPPING

1. Profits derived from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, such profits may be taxed in the other Contracting State from which they are derived provided that the tax so charged shall not exceed :

- (a) during the first five fiscal years after the entry into force of this Convention, 50 per cent, and
- (b) during the subsequent five fiscal years, 25 per cent,

of the tax otherwise imposed by the internal law of that State. Subsequently, only the provisions of paragraph 1 shall be applicable.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of ships.

4. For the purposes of this Article :

- (a) interest on funds connected with the operation of ships in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest; and
- (b) profits from the operation of ships includes profits derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

Article 10 ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary consult each other.

Article 11 DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid

is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1. Subject to the provisions of paragraph 4 of Article 8 and paragraph 4 (a) of Article 9, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other state.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State. But the tax so charged on interest payable in respect of a loan given or debt created after the date of entry into force of this Convention, shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount, if such interest is paid on any loan of whatever kind granted by a bank, and
- (b) 15 per cent of the gross amount in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State, a political sub-division or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any agency of that Government, or by any other resident of that other Contracting State with respect to debt claims of that resident which are financed, guaranteed or insured by the Government of that other Contracting State, a political sub-division or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any agency of that Government, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of the person making the payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, be reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provision of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the

alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

With respect to gains derived by the Danish, Swedish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such proportion of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by Det Danske Luftfartsselskab (DDL), the Danish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State provided that such shares represent at least 10 per cent of the share capital of that company.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State :

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities, in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year of that other State, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provision of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year of that other State, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

4. Where a resident of Denmark derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Scandinavian Airlines System (SAS) consortium, such remuneration shall be taxable only in Denmark.

Article 17

DIRECTORS' FEES & REMUNERATION OF TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Director's fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions or local authorities.

Article 19

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

3. The provisions of Articles 16 and 17 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.

Article 20

STUDENTS

AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on:

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State not exceeding 20000 Danish Crowns or its equivalent in Indian currency during any fiscal year of that other State provided that such employment is directly related to his studies or is necessary for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 22

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by boats engaged in inland waterways transport, and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft and boats, shall be taxable only in the Contracting State in which the enterprise is a resident.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 23

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting State except where express provision to the contrary is made in this Convention.

2. Double taxation shall be avoided in the case of India as follows:

- (a) Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Denmark, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax in Denmark, whether directly or by deduction; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Denmark. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Denmark. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income tax paid in Denmark shall be allowed in the first instance from income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India;

- (b) Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Denmark, India may include

this income or capital in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax which is attributable, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in Denmark.

3. Double taxation shall be avoided in the case of Denmark as follows:

(a) Subject to the provisions of sub-paragraph (c) where a resident of Denmark derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Denmark shall allow:

(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in India;

(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in India;

(b) Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in India;

(c) Where a resident of Denmark derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention shall be taxable only in India, Denmark may include this income or capital in the tax base, but shall allow as a deduction from the income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax which is attributable, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in India.

(d) For the purposes of the deduction referred to in sub-paragraph (a), the term "income tax paid in India" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax under the laws of India and in accordance with this Convention for any year but for an exemption from, or reduction of, tax granted for that year under :

(i) Sections 10(4), 10(4A), 10(4B), 10(6) (vii), 10(15) (iv), 10A, 32A, 80-HH, 80-I, 80-J and 80-L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or

(ii) any other provisions which may be enacted hereafter granting a deduction in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of the economic development of India, if it has not been modified thereafter or has been modified

only in minor respects so as not to affect its general character;

(e) For the purposes of deduction referred to in sub-paragraph (a), Indian tax on interest and royalties and fees for technical services shall in no case be considered as having been paid at a rate of less than

(i) in the case of interest —

(a) 10 per cent in the case of banks; and

(b) 15 per cent in other cases; and

(ii) 20 per cent in the case of royalties and fees for technical services.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 10, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 7 of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

ARTICLE 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only

for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

ASSISTANCE IN COLLECTION

1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Convention relates, in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the State making the request.

2. In the case of a request for enforcement or collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its taxes.

3. In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes to the Danish Tax Directorate, Statesskattedirektoratet, Post box 100, DK—3460 Birkerød, Denmark and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

4. In the case of Danish tax, the request will be sent by the Danish Tax Directorate, to the Central Board of Direct Taxes, (FTD), Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 110001, India and will be accompanied by

such certificate as is required by the laws of Denmark to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

5. Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.

6. A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

7. The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs 1, 2 and 5 of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request but it shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.

ARTICLE 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 29

TERRITORIAL EXTENSION

1. This Convention may be extended by common agreement, either in its entirety or with such modifications as are agreed upon to part of the territory of Denmark which is specifically excluded from the application of the Convention and which imposes taxes substantially similar in character to those to which the Convention applies. Any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions, including conditions as to termination, as may be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels or in any other manner in accordance with their constitutional procedures.

2. Unless otherwise agreed by both Contracting States, the termination of the Convention by one of them under Article 31 shall also terminate, in the manner provided for in that Article, the application of the Convention to any part of the territory of Denmark to which it has been extended under this Article.

ARTICLE 30

ENTRY INTO FORCE

1. The Governments of the Contracting States shall notify to each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2. This Convention shall enter into force on the date of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in respect of tax for the income year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the latter of the notifications referred to in paragraph 1 is given, and subsequent income years.

3. The Agreement between the Governments of India and Denmark for the Avoidance of Double Taxation of Income, signed at Copenhagen on the 16th September 1959, shall cease to have effect at the time when the provisions of this Convention shall be effective in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.

ARTICLE 31 TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notification of termination on or before the thirtieth day of June of any calendar year following after the period of five years from the year in which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect, in respect of tax for the income year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notification is given and subsequent income years.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Copenhagen this 8th day of March one thousand nine hundred and eightynine in the Hindi, Danish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

Sd/-

R. C. SUKLA

For the Government of
Republic of India

Sd/-

JENS ROSHAN

For the Government of the
Kingdom of Denmark

PROTOCOL

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark :

Having entered into a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income and Capital :

Having agreed, at the time of signing the said Convention, on the following provisions which shall constitute an integral part thereof :

(1) For the purposes of paragraph 3 (e) of Article 23, it is understood that the rates of tax specified therein shall in no case exceed the rate of withholding tax applicable to

such categories of income under the Indian tax laws.

- (2) For the purposes of Article 27, a request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall not be made unless such taxes aggregate to 2000 Danish Crowns or its equivalent in Indian currency or more.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Copenhagen this 8th day of March one thousand nine hundred and eightynine in the Hindi, Danish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

Sd/-

RC. SUKLA

For the Government of
the Republic of India

Sd/-

JENS ROSHAN

For the Government of
the Kingdom of Denmark

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention :

1. The Convention has been extended to apply in its entirety to the territory of the Faroe Islands.
2. In the Convention the terms "the Kingdom of Denmark" and "Denmark" shall also apply to the Faroe Islands unless the context otherwise requires.
3. The taxes which in pursuance of the present Protocol are the subject of the Convention shall include the following taxes which are levied on the Faroe Islands :—
 - (a) the provincial income-tax (skatten til landskassen) ;
 - (b) the municipal income-tax (den kommunale indkomstskat);
 - (c) the church tax (kirkeskatten) ;
 - (d) the tax on dividends (udbytteafgiften) ;

- (e) the tax on profit from real estate (ejendomsavanceafgiften) ;
- (f) the tax on royalty (royaltyafgiften).

4. The term "competent authorities" means in the case of the Faroe Islands the Faroe Local Government or the authority which on behalf of the Faroe Local Government has been authorized to handle questions with reference to the Convention.

5. This Protocol shall enter into force on and have effect from the same date as the Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Copenhagen this.....8th day of March one thousand nine hundred and eightynine in the Hindi, Danish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

Sd/-

R. C. SUKLA

For the Government of
Republic of India

Sd/-

For the Government of the
the Kingdom of Denmark
JENS ROSMAN

[Notification No. 8460/F. No. 505/3/81-F.T.D.]

धन-कर

सा.का.नि. 854(अ) --केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 14क के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फरोआइलैंड को एक व्यक्ति-रूपी देश घोषित करती है।

[(अधिनियम सं. 8461) का सं. 505/3/81-फ.टी.डी.]

पी.के. अप्पाचू, संयुक्त सचिव

WEALTH TAX

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby declares Denmark to be a reciprocating country for the purposes of that Act.

[Notification No. 8461/F. No. 505/3/81-FTD]

P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

